

प्रेषक,

अनूप कशाबन्,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मेलाधिकारी,
हरिद्वार।

शहरी विकास अनुभाग-1

देहरादून : दिनांक : 14 जनवरी, 2010

विषय: आगामी कुम्भ मेला, 2010 के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-58 के कि.मी. 207 से भीमगौड़ा तक पंतद्वीय पार्किंग हेतु अंकर पास ब्रिज के निर्माण कार्य हेतु द्वितीय एवं अन्तिम किस्त की धनराशि के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

सहोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-146/IV(1)/2009-35(कुम्भ)/2009, दिनांक 15.06.2009 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा अधिरासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार द्वारा उक्त कार्य हेतु प्रस्तुत आगणन रु. 61.25 लाख के सापेक्ष तयानीकी परीक्षणोपरान्त संस्तुत रु. 42.78 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति देते हुए, वित्तीय वर्ष 2009-10 में रु. 40.00 लाख (रु. चालीस लाख मात्र) की धनराशि अब तक व्यय हेतु अवमुक्त की जा चुकी है। तत्काल में आपके पत्र संख्या 4232/कुम्भ-2010/लेखा-उपयोगिता प्रमाण पत्र, दिनांक 09.01.2010 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि श्री राज्यपाल, उक्त कार्य हेतु समस्त/अवशेष रु. 2.78 लाख (रु. दो लाख अठ्ठातर हजार मात्र) की धनराशि को वित्तीय वर्ष 2009-10 में व्यय किए जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों की साथ साहस स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का, पूर्व स्वीकृत धनराशि के पूर्ण उपयोग के बाद ही दूसरी किस्त का कोषागार से आहरण किया जाएगा। यदि पूर्व अवमुक्त धनराशि बैंक में रखकर उस पर व्याज अर्जित हुआ है तो उस समस्त अर्जित व्याज को राजकोष में ट्रेजरी चालान से जमा कराके उसकी फोटोप्रति शासन को अविलम्ब उपलब्ध करवाने का वास्तव मेलाधिकारी का ही होगा।
2. चूंकि निविदा में प्राप्ता एल-1 निविदा (न्यूनतम निविदा) आधार पर स्वीकृत लागत से कम धनराशि व्यय होना सम्भावित है। अतः न्यूनतम सम्भावित व्यय के अनुसार ही कम धनराशि आहरण की जाएगी तथा आहरित धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि बचत होती है तो उसे तत्काल राजकोष में जमा किया जाएगा।
3. उक्त धनराशि के पूर्ण उपयोग का निम्नानुसार उपयोगिता प्रमाणपत्र उपलब्ध कराए जाने के उपरान्त ही शेष धनराशि अवमुक्त किए जाने पर विचार किया जाएगा।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि के विपरीत न्यूनतम निविदा (एल-1) का विवरण देकर उसी के अनुसार ही अवमुक्ति हेतु अवशेष धनराशि का ही कोषागार से आहरण किया जाएगा।
5. उक्त कार्य इसी धनराशि से पूर्ण किया जाएगा और आगणन का पुनरीक्षण किसी भी दशा में अनुमन्य न होगा।
6. योजनागतगत प्रस्तावित कार्यों का निकटता से पर्यवेक्षण किया जाए। इसके लिए यथाआवश्यकता निगरानी समिति का गठन कर लिया जाए।
7. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व शासनादेश संख्या 475/XXV(7)/2008 दिनांक 15 दिसम्बर, 2008 की व्यवधानुसार निर्धारित प्रारूप पर अनुबन्ध निषादन की कार्यवाही सुनिश्चित कर ली जाएगी।

8. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.3.2010 तक उपयोग करके कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जाएगा।
9. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता के लिए संबंधित अधिशासी अभियंता/मेलाधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
10. उक्त धनराशि का आहरण मेलाधिकारी, हरिद्वार के आहरण वितरण जोड से किया जाएगा।
11. शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध उक्त शासनादेश दिनांक 15.06.2009 के अनुसार यथावत लागू रहेंगे।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय शासनादेश संख्या 1814/IV(1)/2009-39 (सा)/2008-टीसी दिनांक 24 नवम्बर, 2009 के द्वारा मेलाधिकारी के नियुक्ति पर रखी गई धनराशि रु. 100 करोड़ के समेक आहरित कर किया जाएगा तथा पुस्तिका तदस्थान में वर्णित लेखाशीर्षक में किया जाएगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के आ.सं. 819/XXVII(2)/2009 दिनांक 13 जूनवरी, 2010 में प्राप्त जनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भयदीय,

(अनूप त्रिपाठी)
प्रमुख सचिव।

संख्या : 57 (1)/IV(1)/2010 तद्विनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा. शहरी विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. महालेखाकार (ऑडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त, गवर्नल मण्डल, पौड़ी।
7. जिलाधिकारी, हरिद्वार/देहरादून।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार।
9. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी.ओ. में इसे शामिल करें।
11. अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनूप त्रिपाठी)
प्रमुख सचिव।